

(b) if so, the decision taken by the Government in the matter ; and

(c) whether Government have assessed the number of freedom fighters eligible for the grant of such pension and the expenditure involved in it ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GIRH MANTRALAYA MEN RAJYA MANTRI) (SHRI K. C. PANT) : (a) Such a memorandum has been received from the Tamilnad Freedom Fighters Committee.

(b) and (c) As the relief and rehabilitation of freedom fighters is mainly the responsibility of State Governments who have their own schemes of pension, it would be for the State Government to consider the possibility of enhancing the amount of pension.

Increase in Price of Cotton

371. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of FOREIGN TRADE (VIDESH VYAPAR MANTRI) be pleased to state :

(a) whether Government have recently increased the price of cotton for the current year ; and

(b) if so, the details thereof and the reaction of cotton producers, dealers and manufacturers in this regard ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (VIDESH VYAPAR MANTRALAYA MEN UP-MANTRI) (SHRI A. C. GEORGE) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Indo-French Trade Agreement

372. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of FOREIGN TRADE (VIDESH VYAPAR MANTRI) be pleased to state :

(a) whether the terms of the agreement regarding trade between India and France have been extended ;

(b) if so, the details regarding the export of Indian manufactured goods ; and

(c) the amount of foreign exchange likely to be earned through this agreement ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (VIDESH VYAPAR MANTRALAYA MEN UP-MANTRI) (SHRI A. C. GEORGE) :

(a) Yes, Sir. The Indo-French Trade Arrangement entered into by the Governments of India and France in October, 1959 have been last extended for one year from 1st January, 1971 by the Protocol of the Indo-French Joint Economic Commission, signed in New Delhi on 24th April, 1971.

(b) To promote exports of Indian manufactured products the Protocol of the Indo-French Joint Economic Commission envisage, formulation and implementation of a Commercial Development Programme with the appropriate French assistance, the details of which will be settled in due course.

(c) The present Agreement is on the pattern of our Trade Agreements/Arrangements with free market economy countries and does not involved import/export commitment. It is, therefore, not possible to anticipate the foreign exchange earnings.

बीकानेर डिवीजन में डाकघरों का किराये के मकान में होना

373. श्री पन्नालाल बारूपाल : क्या सचर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बीकानेर डिवीजन में नगरो तथा मडियो में कितने ऐसे डाकघर है जो अभी भी किराये के मकानों में कार्य कर रहे है ;

(ख) जहाँ ऐसे डाकघर कार्य कर रहे हैं वहा प्रत्येक मकान का किराया क्या है और मकान मालिकों को अब तक किराये के रूप में कितनी राशि दी गई है ;

(ग) ऐसे कितने डाकघर है जिनको 1971-72 के दौरान डाक-तार विभाग द्वारा निर्मित मकानो में स्थानान्तरित किया जाना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) यदि विभाग डाकघरों के लिए स्वयं अपने भवन बना रहा है तो ऐसे स्थानों के नाम

क्या हैं जिनको इस मामले में प्राथमिकता दी जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहू-गुणा) : (क) नगरों में 24
मंडियों में 25

(ख) सूची विवरण में दी गई है जो सभा पटल पर रख दिया गया है। [प्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या LT-186/71]

(ग) (i) कोई नहीं।

(ii) कारण—डाकघर के लिये कोई भवन इस समय निर्माणाधीन नहीं है।

(घ) बीकानेर डिवीजन में निम्नलिखित स्थानों पर विभागीय इमारतों का निर्माण करने की योजना है :

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. पदमपुर | 2. रायसिंह नगर |
| 3. हनुमानगढ़ जं० | 4. सांगरिया |
| 5. नोखा | 6. श्रीकारनपुर |
| 7. भाद्रा | 8. हनुमानगढ़ |
| 9. देशनोक | |

राजस्थान के बीकानेर डिवीजन के डाक-तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

374. श्री पन्थालाल बाबू पाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में प्रत्येक डाक तार-घर में अधिकारियों और कर्मचारियों की अलग-अलग कितनी संख्या है।

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों के पास सरकारी रिहायशी क्वार्टर हैं और कितने किराये के मकानों में रहते हैं ;

(ग) क्या अधिकारियों और कर्मचारियों की भावास सम्बन्धी समस्या को सुलझाने की बात को दृष्टि में रखते हुये उनके मंत्रालय का विचार रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण कराने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने क्वार्टर बनाने का विचार है और वे कहाँ बनाये जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहू-गुणा) : (क) सूचना विवरण में दी गई है जो सभा-पटल पर रख दिया गया है। [प्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या LT-187/71]

(ख) (i) वे अधिकारी	वे कर्मचारी
जिन्हें सरकारी रिहा-	जिन्हें सर-
यशी मकान	कारी मकान
दिये गये हैं	दिये गये हैं

—कोई नहीं—

31

(ii) वे अधिकारी जिन्हें	वे कर्मचारी
किराये के मकान	जिन्हें किराये
दिये गये हैं	के मकान दिये
	गये हैं

3

51

शेष कर्मचारी स्वयं ही व्यवस्था करके मकानों में रह रहे हैं।

(ग) जी हां। बीकानेर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में।

(घ) बीकानेर में 42, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में प्लाटों के अधिग्रहण के पश्चात क्वार्टरों के निर्माण की योजना की अभी अन्तिम रूप देना बाकी है।

रूस के साथ रूई व्यापार समझौता

375. श्री ईश्वर चौधरी :

श्री प्रार० बी० बड्डे :

श्री सारतम्ब सिंह :

क्या बिबेक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूई के आयात के लिए रूस के साथ हाल में एक व्यापारिक समझौता किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारत के साथ हुए